THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARI): (a) and (b). The percentage of advances by public sector banks to agriculture to their aggregate advances was 14.6 per cent as at the end of December 1979 which increased to 15.5 per cent as at the end of December 1980. The total agricultural credit increased from Rs. 2583 crores as at the end of December 1979 to Rs. 3460 crores as at the end of December, 1980. The banks have been directed that their agricultural advances should constitute 18 per cent of their total advances by 1985. This is an all-India target and therefore, no State-wise comparisons are made in the banks performance in this regard. The agricultural credit of public sector banks in the State of Orissa was Rs. 53.01 crores as at the end of December 1979 which increased to Rs. 78.55 crores as at the end of December 1980. These constituted 33.2 per cent and 25.6 per cent respectively of the total advances of public sector banks in Orissa. The banks have also been advised that their advances to the weaker sections in the agricultural sector should reach the level of 50 per cent of their direct agricultural advances by 1983.

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण न देना

4208. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

'(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिनकी शाखाओं ने ऋण देने से इन्कार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उन ऋण नियंत्रणों के परिप्रेक्ष्य में जो कि बकों को पिछले वर्ष लागू करने पड़े थे, बैंकों से ताजा ऋण की उपलब्धता में कमी के बारे में कुछ सामान्य शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थीं जिनमें कुछेक राज्य सरकारों से भी मिली थीं। बैंकों का यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई थी कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और 20-सूत्रीय कार्यक्रम के छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण का प्रवाह बनाए रखा जाए। यह तथ्य कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के अग्रिम दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के 2643 करोड़ रुपये से बढ़ कर दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक 3600 करोड़ रुपये हो गये अथवा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ प्राप्तकर्ताओं के वास्ते वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा जुटाए गए सावधि ऋण 1980-81 में 207 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1981-82 में 484 करोड़ रुपये हो गए, दर्शाते हैं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बैंक सक्रिय सहयोग दे रहे हैं।

विजन स्कोप इंडिकेटर से लैस हवाई अड्डे

4209. **श्री निहाल सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जिन पर विजन स्कोप "इंडिकेटर" और दूरी मापक उपकरण लगे हुए है और उनके नाम क्या हैं जिन पर ये उपकरण नहीं लगे हुए हैं ;

(ख) क्या कुछ हवाई अड्डों पर "विजन स्कोप इंडिकेटर" खराब पड़े हैं और दूरी मापक उपकरण नहीं लगाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या है ?